## आजादी के बाद से अब तक का सबसे स्वच्छ है गंगाजल

# स्वच्छता व तकनीक से काबू में आया जापानी इंसेफलाइटिस

## बोले योगी, तराई क्षेत्र में बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण रही है यह बीमारी

जासं, वाराणसी : आइआइटी, बीएचयू में शनिवार को भावी इंजीनियरों व पुराछात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रयागराज में कुंभ के मद्देनजर कई स्थानों पर एसटीपी बनाकर गंगा व सहायक नदियों में गिरने वाले गंदे पानी को रोका गया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास का ही नतीजा रहा कि गंगा का पानी आजादी के बाद से लेकर अब तक का सबसे साफ पानी है। कहा जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी चुनौती है। विकास के नाम पर सबसे ज्यादा कहर तालाबों, नहरों, नदियों व अन्य जल स्त्रोतों पर ही बरपाया गया। जल स्त्रोत समाप्त होना व नदियों की अविरलता का बाधित होना मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट है। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण के लिए सस्ती तकनीक ईजाद करने की अपील की। कहा तकनीक जितनी सरल होगी, आमजन के लिए उतनी ही उपयोगी साबित होगी।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : तराई क्षेत्र में अबूझ पहेली जापानी इंसेफलाइटिस को हराने में तकनीक के साथ ही साफ-सफाई का अहम योगदान है। पिछले एक वर्ष में इस अबूझ बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है। यह बातें आइआइटी, बीएचयू के शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कही।

तकनीक व स्वच्छता की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से गोरखपुर क्षेत्र में प्रतिवर्ष 700-800 बच्चे अनजान बीमारी के कारण दम तोड़ रहे थे। 1978 में पहली बार इस बीमारी की पहचान हुई। पूर्ववर्ती सरकारों ने जापानी इंसेफलाइटिस नाम की इस बीमारी के इलाज की व्यवस्था तो की, मगर कारण जानने की जहमत नहीं उठाई। तकनीक की बदौलत जहां इसकी वजह सामने आई, वहीं साफ-सफाई के माध्यम से एक साल के भीतर ही इस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। कई तरह के शोध व सर्वे कार्यों के बाद निष्कर्ष निकला कि शुद्ध पेयजल और स्वच्छता अपनाकर इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अप्रैल 2017 में मैंने तराई क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान छेड़ा, जिसका नतीजा रहा कि पिछले एक वर्ष में गोरखपुर मेडिकल कालेज में इस बीमारी से ग्रसित सिर्फ 86 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से महज 6 की ही मौत हुई है। यानी साफ-सफाई अपनाकर जहां बीमारियों से बचा जा सकता है, वहीं दवा-इलाज पर होने वाले खर्च को भी घटाया जा सकता है।

आइआइटी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री को सुनते पुरातन छात्र • जागरण

### स्वच्छता को पीएम की पहल बनाएं साढ़े नौ करोड़ शौचालय

जासं, वाराणसी : मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विद्यालयों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। विद्यार्थी के नाखून, बाल कटे हैं या नहीं, इस पर शिक्षक की पैनी नजर रहती थी। साथ ही साफ-सुथरे ड्रेस, खाने से पहले व शौच के बाद अच्छी तरह हाथ धुलने के बारे में भी बराबर चेताया जाता था। परिवार के लोग भी इन सब पर बराबर नजर रखते और स्वच्छता सुनिश्चित करते थे। समय बदला और वर्तमान में न तो विद्यालय और न ही परिवार का ध्यान इन बातों पर रह गया। आखिरकार प्रधानमंत्री को स्वच्छता के लिए देशव्यापी अभियान चलाना पड़ा। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत विगत साढ़े चार वर्षों में 9.5 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए। इससे जहां नारी गरिमा की रक्षा हुई, वहीं दवा के खर्च में भारी कमी आई।

## तकनीक ने रोका भ्रष्टाचार गरीबों को मिला उनका आहार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाकर गरीबों के राशन की लूट मची थी। सस्ता खाद्यान्न कालाबाजारी के लिए बड़े पैमाने पर बांग्लादेश व नेपाल भी भेजा जाता था। गरीबों के निवाले पर डाका डालने वालों पर नकेल लगाना तकनीक के जरिए ही संभव हो सका है। आधार के जरिए प्रदेश में करीब 60 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ में आ सके हैं। यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आइआइटी, बीएचयू के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोटे की कुल 80 हजार दुकानें हैं। इनमें से शहरी क्षेत्र के करीब 13 हजार दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगाई गई हैं। राशन कार्ड को आधार से लिंक कर राशन की चोरी रोकी गई। पिछले एक साल में करीब 110 करोड़ रुपये के राजस्व की बचत भी हुई है। जल्दही प्रदेश के 80 हजार दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगा दी जाएंगी, जिससे सालाना करीब 500-700 करोड़ रुपये का राजस्व बचेगा।

### सहूलियत

- बांग्लादेश व नेपाल जाता था गरीबों के मुंह का निवाला
- आधार के जरिए पकड़े गए 60 लाख फर्जी राशन कार्ड

### एलईडी स्ट्रीट लाइट ने बचाए 250 करोड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरल तकनीक की अहमियत पर प्रकाश डाला। बताया कि प्रदेश में 16 लाख हैलोजन स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदला जा रहा है। पहले चरण में आठ लाख लाइटें बदलने का परिणाम रहा कि सरकार को 250 करोड़ रुपये के राजस्व की बचत हुई।